रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

GOVERNMENT OF INDIA

सं. 12] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2001/पौष 15, 1922

No. 12] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2001/PAUSA 15, 1922

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2001

का. आ. 13 (अ).— यतः निम्नलिखित दो अधिसूचनाओं में उल्लिखित भूमि का 'हरित' क्षेत्र के रूप में विकास और अनुरक्षण करने के लिए तथा इस प्रयोजन हेतु यथा अपेक्षित कदम उठाने के लिए यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस शर्त पर सौंपी गयी थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उक्त भूमि पर न तो कोई भी निर्माण करेगा अथवा न ही इसकी इजाजत देगा और दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित होने पर उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को अपेक्षानुसार केन्द्र सरकार को सौंप देगा।

1. एस.ओ. 2190 दिनांक 20 अगस्त, 1974 (48 गांव)
2. टी.सी.ओ./82/47 दिनांक 6 मई, 1982 (23 गांव)

2. और यतः केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त दो अधिसूचनाओं द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गयी भूमि के एक हिस्से को वापस लेकर नीचे दी गयी सारणी के अनुसार अपर आयुक्त (स्लम एण्ड जे जे), दिल्ली नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया है :-

क.सं.	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बि. बि. में)
1.	मदनगिर	191	12-00
2.	मदनपुर खादर	768	1-18
		775	4-10

क्र.सं.	गांव का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बि. बि. में)
		776	3-10
		777	3-07
		778	3-09
		779	131-15
		784	425-01
		785	5-05
		789	2-08
		790	5-13
		791	6-00
			592-16
3.	मादीपुर	1614/705 मिन	8-01
4.	ख्याला	10/1 मिन	1-04
		2 मिन	1-04
		9	4-16
		10	4-16
			12-00
5.	केसो पुर	7/10	4-16
6.	नजफगढ़	49/05	3-16
		15	6-00
		14	1-05
		50/1/1	1-05
		12	6-00
		13/1	0-04
			18-10
7.	हैबत पुर	6/25	4-16
		8/05	4-16
		17/1/1	2-00
		3/5	3-18
			15-10
8.	सराय पीपल थला	93	5-15
9.	बक्का	715/379	1-10
		717/379	1-12
		717/318 200	1-00
		702/493	2-05
		703/493	2-01

294	4-00
297	18-08
298	7-17
305	3-06
306	3-07
308	73-11
495/309	17-08
310	5-08
	147-13
कुल योग	817-1

(170 एकड़ लगभग)

3. इसके अलावा, अपर आयुक्त (स्लम एण्ड जे जे), दिल्ली नगर निगम पैरा-2 में उल्लिखित भूमि का उपयोग, सरकारी भूमि से हटाए गये लोगों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर करेंगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होंगी :-

क. दिल्ली नगर निगम भूमि का तत्काल कब्जा लेकर उसकी देखभाल, प्रबन्ध और विकास की जिम्मेदारी लेगी।

ख. स्लम विभाग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुदेशों अथवा निबन्धन और शर्तों के अनुसार पुनर्वास प्रयोजन हेतु इस भूमि के उपयोग बाबत मंत्रालय से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करेगा।

ग. भूमि खाली कराने के मामले में केन्द्र सरकार की भूमि को प्राथमिकता दी जाएगी।

घ. अतिरिक्त आयुक्त (स्लम एण्ड जे जे), दिल्ली नगर निगम स्थल की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए उसके फोटोग्राफ और वीडियो पिक्चर लेकर एक सम्पत्ति सूची तैयार करेंगे। पहले से जो लोग काबिज हैं उनका समुचित रिकार्ड रखा जाएगा और उनकी समस्याओं का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बाद में निराकरण किया जाएगा। इस भूमि का कब्जा लेने में किसी भी हालत में विलम्ब न किया जाए।

ड. केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली नगर निगम उक्त भूमि अथवा उसके किसी हिस्से को केन्द्र सरकार को सौंप देगी।

4. इस पर अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार का उनकी डायरी सं. 2746-एफ दिनांक 22-12-2000 के तहत अनुमोदन प्राप्त है।

[सं. जे-13021/3/70-एल 1-पार्ट]

मधुकर एस. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2001

S. O. 13(E).—Whereas the lands specified in the following two notifications were placed at the disposal of the Delhi Development Authority for the purposes of development and maintenance of the said lands as 'green' and for taking such steps as may be required to serve the said purpose subject to condition that the Delhi Development Authority shall not make, or cause, or permit to be made any construction on the said lands and that the Delhi Development Authority shall when required by the Central Govt. so to do, replace the said lands on any portion thereof as may be so required, at the disposal of the Central Govt:-

i) S.O.2190 dated 20th August,1974 (48 villages)
ii) T.C.O./82/47 dated 6th May,1982 (23 villages)

2. And Whereas the Central Govt. has decided to resume part of the lands placed under the disposal of Delhi Development authority vide above mentioned two notifications and place the same at the disposal of the Additional Commissioner(Slum & JJ), Municipal Corporation of Delhi as per the schedule given below:-

S No.	Name of Villages	Khasra No.	Area(in B.B.)
1	Madangir	191	12-00
2.	Madanpur Khadar	768	1-18
		775	4-10
		776	3-10
		777	3-07
		778	3-09
		779	131-15
		784	425-01
		785	5-05
		789	2-08
		790	5-13
		791	6-00
			592-16

S.No.	Name of Villages	Khasra No.	Area(in B.B.)
3.	Madipur	1614/705 Min	8-01
4.	Khayala	10/1 Min	1-04
		2 Min	1-04
		9	4-16
		10	4-16
			12-00
5.	Keso Pur	17/10	4-16
6.	Nazafgarh	49/05	3-16
		15	6-00
		14	1-05
		50/1/1	1-05
		12	6-00
		13/1	0-04
			18-10
7.	Habat Pur	6/25	4-16
		8/05	4-16
		17/1/1	2-00
		18/5	3-18
			15-10
8.	Sarai Pipal Thala	93	5-15
9	Dhaka	716/379	1-10
		717/379	1-12
		317/318/200	8-00
		702/493	2-05
		703/493	2-01
		294	4-00
		297	18-08
		298	7-17
		305	3-06
		306	3-07
		308	73-11
		495/309	17-08
		310	5-08
			147-13

GRAND TOTAL= 817-1
(170.0 Acres)
approx)

3. Further, the Addl.Commissioner (Slum & JJ), Municipal Corporation of Delhi would utilise the lands mentioned at para-2 above for re-settlement of squatters from Central Govt. lands on such terms & conditions as may be prescribed by the Central Govt. which would, inter-alia, also include the following:-

(a) The MCD shall take immediate possession of the lands and assume the responsibility for their care, management & development.

(b) Slum Department will take specific approval of the Ministry in regard to utilisation of these lands for the purpose of re-settlement, subject to the instructions or terms & conditions that the Central Govt. may prescribe.

(c) Priority in respect of clearance would be given to the Central Govt. lands.

(d) Additional Commissioner (Slum & JJ), MCD shall make an inventory of the lands, take photographs & video pictures indicating the present condition at the site. Whatever squatting has taken place earlier, it should be properly recorded and the problems in this regard would be settled by the Delhi Development Authority subsequently. The possession of these lands should not be delayed in any case.

(e) The MCD shall when required by the Central Govt. so to do, replace the said lands or any portion thereof as may be so required, at the disposal of the Central Govt.

4. This has the concurrence of AS&FA vide his Dy.No. 2746-F dated 22.12.2000.

[No. J-13021/3/70-L1-Pt.]

MADHUKAR S. GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.